भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1524

दिनांक 31.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

आंध्र प्रदेश में ईवी चार्जिंग अवसंरचना

1524 श्री विजय चिंताकायला:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम ई-ड्राइव और एफएएमई जैसी योजनाओं के अंतर्गत सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु, राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों सहित, उपयुक्त स्थलों की पहचान करने में केंद्र सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच समन्वय की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय आंध्र प्रदेश की केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत फास्ट चार्जरों की स्थापना में तेजी लाने में सहायता हेतु किसी एकल-खिड़की स्वीकृति तंत्र, राज्य-केंद्र समन्वय मंच, या समर्पित नोडल सहायता का विचार रखता है; और

(ग) आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की मांग में अनुमानित वृद्धि का समर्थन करने के लिए ग्रिड की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) के साथ समन्वय को सुदृढ़ करने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने हेतु परिकल्पित हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सहित देशभर में इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) की स्थापना हेतु 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड (एनआरईडीसीएपी) को ईवीपीसीएस की स्थापना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत भारी उद्योग मंत्रालय ने स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार के 577 ईवी चार्जरों की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को लगभग 39.79 करोड़ रुपए की कुल सहायता के साथ अनुमोदित किया है।

फेम-II स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) की स्थापना हेतु 912.50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जिसमें से 873.5 करोड़ रुपए तीन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी), नामतः बीपीसीएल, आईओसीएल तथा एचपीसीएल को स्वीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त, फेम-II स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार कोई आवंटन नहीं किया गया है। तीनों ओएमसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, फेम-II स्कीम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में कुल 538 इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 469 ईवीपीसीएस दिनांक 01.07.2026 की स्थिति के अनुसार प्रचालन में हैं।

(ख): पीएम ई-ड्राइव स्कीम का पोर्टल राज्य नोडल एजेंसियों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) की स्थापना के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में नामित किया गया है।

(ग): विद्युत समवर्ती सूची का विषय है तथा विद्युत वितरण का कार्य राज्य सरकारों के अधीन विद्युत वितरण उपयोगिताओं द्वारा किया जाता है। अपने-अपने कार्यक्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग संबंधी संभावित मांग को पूरा करने के लिए उप-पारेषण तथा वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु आवश्यक उपाय करना संबंधित वितरण/पारेषण उपयोगिता की जिम्मेदारी है।

******